deposit for the local PCOs. But, so far as the STD/ISD/PCO booths are concerned, till now, only priority is being given to them. What I said earlier was that we have been examining the case very sympathetically. I think, within a short time, the Government will decide on some positive things.

Sale of Foodgrains to Poultry Industry

*724. DR. DASARI NARAYANA RAO: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the status of issuable and non-issuable stocks of foodgrains in FCI godowns of Andhra Pradesh as on the 31st March, 2002, commodity-wise;

(b) whether Government propose to sell foodgrains unfit for human consumption to poultry industry to produce poultry feed on token price to ease the stock position and promote poultry sector in the State; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHANTA KUMAR): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The requisite information about issuable and non-issuable stocks of foodgrains available in FCI godowns in Andhra Pradesh as on 31.3.2002 is given below:

(Figures in MTs)

Sl. No.	Commodity	Issuable stocks	Non-issuable stocks
1.	Wheat	3,31955	1,364
2.	Rice	10,67,081	33
3.	Paddy	191	—

(b) and (c) The disposal of damaged foodgrains, unfit for human consumption, is a continuous process. Such stocks, including foodgrains fit for poultry feed, are disposed of as per the prescribed procedure. The poultry industry is also eligible to purchase such stocks.

DR. DASARI NARAYANA RAO: Sir, the hon. Minister has laid the statement on the Table, giving the status of the stocks lying in the Food Corporation of India godowns of Andhra Pradesh. Sir, in this, the issuable stock of rice is 10,67,081 tonnes. I would like to know from the hon. Minister how old the stock is, whether it is one-year-old or two-year-old or three-year-old.

With regard to wheat, there is a stock of 3,31,955 tonnes lying in the godowns of Andhra Pradesh. I would like to know from the hon. Minister whether this wheat is procured only from Andhra Pradesh or from elsewhere—I would like to have this information—if so, from which State are you procuring? In this, there is a stock of 1,364 tonnes of wheat which is non-issuable. Why did it turnout to be non-issuable? was it kept in the open or there are other reasons?

I would like to get answers to all my questions from the hon. Minister. Thank you.

श्री शांता कुमार: सभापति जी, जो इनफॉर्मेशन दी गई है, उसके मुताबिक हमने बताया कि इश्यूएबल स्टॉक कितना है। जहां तक आंध्र प्रदेश में व्हीट का सवाल है, वहां तो व्हीट प्रोक्योर होता नहीं है। मुख्य रूप से तीन-चार प्रदेशों में हम व्हीट प्रोक्योरमेंट करते हैं और वहां पर जब भंडार बहुत अधिक हो जाता है तो हम अन्य प्रदेशों में भेजते हैं। अन्य प्रदेशों में भी उसका ऑफटेक किसी सीमा तक होता है। हमारे पास जो इश्यूएबल स्टॉक है, यह कितने साल का कौन सा है, यह सूचना तो अभी मेरे पास नहीं है। मैं सूचना प्राप्त करके माननीय सदस्य को भिजवा सकता हूं। इतना जरूर है कि जो भी स्टॉक हमारे पास वहां पर है, उसमें से केवल 1364 मीट्रिक टन व्हीट और 33 मीट्रिक टन चावल ऐसा है जो हमारे पास नॉन-इश्यूएबल स्टॉक है। एक निश्चित प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि यह अनाज जो है, यह इश्यू करने योगय नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें खराब अधिक है, तो उसको अलग कर दिया जाता है, वह पी॰डी॰एस॰ में इश्यू नहीं किया जाता और उसको डिसपोज़ ऑफ करने की एक निश्चित प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में टेंडर करके अन्यान्य तरीकों से इसको खाने के लिए नहीं, अन्य बातों के लिए हम इश्यू करते रहते हैं। चूंकि हमारे पास लगभग 580–590 लाख टन अनाज है तो अलग-अलग स्थानों पर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जो-जो अनाज खराब हो जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। वह नॉन-इश्यूएबल होता है और उसको डिसपोज़ ऑफ करने की जो प्रक्रिया है, उसके मुताबिक डिसपोज़ ऑफ कर दिया जाता है।

DR. DASARI NARAYANA RAO: Sir, I am happy that the hon. Minister assured me that he would send the statement with regard to the age of rice in our godowns.

Sir, my second supplementary is, Andhra Pradesh is leading in poultry industry and we are exporting eggs and chicken. I specifically asked the hon. Minister, 'Whether the Government propose to sell foodgrains unfit for human consumption to poultry industry to produce pultry feed on token price...' This was my question. But, unfortunately, the hon. Minister, instead to giving a clear-cut reply, stated, 'The poultry industry is also eligible to purchase.' So, I would like to know from the hon. Minister whether he is serious to help the poultry industry by giving them non-issuable foodgrains at a subsidised rate, because these foodgrains are unfit for human consumption. Could he give these foodgrains at a subsidised rate to encourage the poultry industry?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, जहां तक नॉन-इश्यूएबल स्टॉक हमारे पास होता है, उसको हम एक निश्चित प्रक्रिया के मुताबिक डिसपोज़ ऑफ करते हैं और कोई भी उसको ले सकता है। माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की है, उस चिंता में मैं उनके साथ शामिल हूं। हमें वहां के एक-दो आर्गेनाइज़ेशन्स की ओर से पत्र आए हैं। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री जी की ओर से पत्र आया है, हमारी ही सरकार के कुछ और मंत्रियों ने मुझे लिखा है कि पोल्ट्री उद्योग के सामने कुछ कठिनाइयां हैं क्योंकि जो अन्यान्य अनाज मेज़ इत्यादि है, वह अधिक महंगा हो गया है इसलिए एक रिप्रेज़ेंटेशन आया है हमारे पास। उसमें उन्होंने यह मांग की है कि इस प्रकार का हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है, उसको कुछ रियायती दर पर पोल्ट्री उद्योग को दे दिया जाए। एक और मांग आई है हमारे पास कि हमारे पास जो अन्यान्य अनाज है, गेहूं के बारे में उन्होंने कहा कि गेहूं को एक्सपोर्ट रेट पर आप पोल्ट्री के लिए दे दीजिए। ये तीन-चार रिप्रेज़ेंटेशन आए हैं जिनके ऊपर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और पोल्ट्री उद्योग के सामने जो कठिनाई है, उस कठिनाई को हम ऐप्रिशिएट करते हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इन सारी बातों पर अतिशीघ्र अनुकूल निर्णय सरकार करेगी।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, the Ministry has supplied 3,31,955 MT of issuable stocks of wheat to Andhra Pradesh. The hon. Minister knows very well that the people of Andhra Pradesh consume more rice than wheat. Sir, hardly 7—10 per cent people consume wheat. They are sending wheat either from Haryana or Punjab to Andhra Pradesh. We know how much transport charges the Government has to bear for transporting wheat from these States to Andhra Pradesh. Keeping this in view, I request the hon. Minister to send rice or paddy instead of wheat to Andhra Pradesh in future. Secondly, the non-issuable stock is 1,364 tonnes. I would like to know from the Minister whether the Government of India will compensate by rice instead of wheat to the extent of 1,364 tonnes.

श्री शांता कुमार: सभापति जी, अन्न की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकारें हमसे जो चाहती हैं, चावल या गंदम वह हम उन्हें भेज देते हैं। माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि तीन-चार प्रदेशों में हम गेहूं प्रिक्योर करते हैं तो वहां कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि रखने की जगह नहीं होती। जब रखने की जगह नहीं होती तो कुछ फूड ग्रेन कहीं-कहीं भिजवा दिया जाता है लेकिन मुख्य रूप से इस बात को देखा जाता है कि जहां आवश्यकता होती है वहीं भेजा जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आवश्यकता नहीं भी होती, जैसे पंजाब, हरियाणा में इतना अधिक प्रिक्योरमैंट हो रहा है कि वहां रखने की जगह नहीं है, इसलिए जहां भी थोड़ी खाली जगह मिलती है वहां भिजवा दिया जाता है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में बाकी सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए सरकार इस सारे के सारे सिस्टम पर बुनियादी तौर पर तैयार करके एक नई फूड ग्रेन पॉलिसी बहुत जल्दी लाना चाहती है। जहां तक आपने आन्ध्र प्रदेश में चावल की बात कही तो वहां जितने चावल की आवश्यकता है उससे अधिक चावल वहां पर है। आज हर प्रदेश में स्थिति यह है कि जितनी जरूरत है, उससे अधिक वहां रखा हुआ है। आज स्थिति यह है कि हम अधिक एलोकेशन सभी स्कीम्स में कर रहे हैं और सभी प्रदेशों से बार-बार कह रहे हैं कि आप जल्दी उठाइए। पिछले साल बी॰ पी॰ एल॰ में जो एलोकेशन की थी उसका ऑफटेक 45 प्रतिशत हुआ था आज अनाज की कमी कहीं नहीं है, आंध्र प्रदेश को जितना चावल चाहिए उतना चावल दे सकते हैं, लेकिन वहां पर्याप्त चावल है परंतु यदि वहां और अधिक आवश्यकता होगी तो वहां भिजवाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार: मंत्री जी, मैंने स्ट्रेट सवाल व्हीट की जगह राइस देने के बारे में पूछा था। वहां से ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीट रखें तो व्हीट कन्जम्पशन कौन लेगा?

In Andhra Pradesh, the wheat consumption is very less. So, I would request you to consider sending rice instead of wheat.

श्री शांता कुमार: सभापति जी, आंध्र प्रदेश में मैदे, सूजी, रोलर फ्लोर मिल्स के लिए व्हीट की डिमांड है। इस डिमांड को मीट करने के लिए वहां व्हीट भेजते हैं लेकिन मैंने कहा कि जितना चावल चाहिए उससे ज्यादा चावल वहां रखा हुआ है, फिर भी जितना चाहिए उससे अधिक वहां भेजने में हमें कोई कठिनाई नहीं है।

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार: मंत्री जी, आंध्र प्रदेश राइस बॉउल है। सभी को मालूम है कि वहां अनाज की कमी नहीं है। गवर्नमैंट जो इश्यू कर रही है उसमें व्हीट कम करके ज्यादा राइस देने की मेरी रिक्वेस्ट है। आप समझ नहीं रहे हैं।

श्री प्रेम चन्द गुप्ता: सभापति जी, अमेरिकी सरकार के कृषि विभाग की एक रिपोर्ट आई है, जो यहां के अखबारों में छपी है। इसमें लिखा है कि अप्रैल, 2003 में पूरी दुनिया में चावल का

जितना स्टॉक होगा उसका एक तिहाई हिस्सा हिन्दुस्तान में होगा। पूरी दुनिया में जितना व्हीट स्टॉक होगा उसका एक चौथाई हिस्सा 2002 में इण्डिया में होगा। 7,70,00,000 टन व्हीट, गेहूं और चावल हमारे डिफ्रेंट गोदाम्स में पड़ा हुआ है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के गोदाम की जो क्षमता है वह साढे पांच करोड़ टन चावल और गेहूं रखने की है जबकि 2003 मे यह रिक्वायरमेंट 7,70,00,000 टन होगी। सभापति जी, 8,900 रुपये ऐवरेज कॉस्ट आई है व्हीट प्रिक्योरमेंट की और 11,300 रुपये चावल प्रिक्योरेमेंट की 'पर टन' आती है। हमारा इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर इसकी पोजीशन देखें तो हमारा 63,00,000 टन फूडग्रेन स्टॉक सड़कों पर पड़ा सड़ रहा है। पिछले दस सालों में 40 हजार करोड़ रुपए का अनाज या तो चोरी हो गया या सड़ गया। मान्यवर, पिछली बार भी माननीय प्रधान मंत्री जी इस हाउस में थे तब यह इश्यू उठा था। मेरा ही एक सवाल था जिसमें मैंने शांता कुमार जी से पूछा था कि यह जो फूड ग्रेन सड़ रहा है इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं तो इन्होंने कहा था कि कोई स्टोरेज की प्राब्लम नहीं है और हम लोगों की एक पालिसी बन रही है और पूरी फैसिलिटीज हो जाएंगी। प्रधान मंत्री जी ने भी लाल किले से कहा कि हम फूड ग्रेन स्टोरेज की एक नेशनल पॉलिसी बना रहे हैं और प्रायोरिटी में यह करेंगे। मान्यवर, जब इतना अनाज सड़ कर जा रहा है, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती है कि यह जो पोल्ट्री फार्म के लिए मांग रहे हैं, या जो गरीब भूखे मर रहे हैं—इस देश के 14 परसेंट लोग, 14 करोड़ इन्सान, जो इस देश के नागरिक हैं... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: क्वेश्चन क्या है?

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: आपको तकलीफहै कोई... **(व्यवधान)** मान्यवर, प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: आधे घंटे तक डिसकशन कीजिए... **(व्यवधान)**

श्री प्रेम चन्द गुप्ता: मान्यवर, मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: आप क्वेश्चन कीजिए ...**(व्यवधान)**

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: सौभाग्य से प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं ...**(व्यवधान)** सिंहल साहब*... जो हमारे नेता जी ने उस रोज कहा था, जहां पर दूसरा चक्कर चलाएंगे ...**(व्यवधान)** तो मान्यवर मैं यह बोलना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले एक दिन इनके नेता ...**(व्यवधान)** आप सुनिए...**(व्यवधान)**

श्री राजू परमार: क्यों उस टाइम पर रेज नहीं करते हो ...**(व्यवधान)** क्यों अपनी बात करते हैं, ...**(व्यवधान)** हंगामा करते हैं ...**(व्यवधान)**

---

* Not recorded.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदय, किसी के पेशे के बारे में सदन में कोई बात नहीं उठायी जा सकती है। यह रूल बुक कहती है।

श्री सभापति: नहीं उठायी जा सकती है, यह ठीक है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: तो क्या बार बार * ...ऐसे कहा जाएगा* ..। यह क्या तमाशा है?

श्री सभापति: यह आप विदड्रा कर लीजिए ...(**व्यवधान**) आप विदड्रा कर लीजिए।

श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता: मेरा क्वेश्चन है ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: नहीं, नहीं यह जो आपने कहा है आप विदड्रा कर लीजिए।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: आदत से मजबूर हैं ...(**व्यवधान**) असल में क्या है ...(**व्यवधान**)

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Is it unparliamentary? (*Interruptions*)* Is it unparliamentary?

Mr. Chairman: No; no. It is not unparliamentary. (*Interruptions*) He can say anything. (*Interruptions*) He can say anything. (*Interruptions*) But personal aspersions should not be made. (*Interruptions*)

श्री दीपांकर मुखर्जी: हमें ये सिखा रहे हैं कि हाउस में क्या बहस हो...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: आप विदड्रा कर लीजिए...(**व्यवधान**) आप कह दीजिए विदड्रा कर लिया.. (**व्यवधान**)

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: What is unparliamentary about it? (*Interruptions*)

Mr. CHAIRMAN: There is nothing unparliamentary. (*Interruptions*) लेकिन परसनल एसपर्शन्स नहीं करने चाहिए...(**व्यवधान**) आप विदड्रा कर लीजिए...

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मैं विदड्रा कर लेता हूं ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: उन्होंने कर लिया है ...(**व्यवधान**)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: He has withdrawn.

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मान्यवर, प्रधान मंत्री जी जब इस हाउस में होते हैं तो हम सब लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी इस दुविधा को सुनें, इस तकलीफ को सुनें क्योंकि समाधान ये ही कर सकते हैं। 40 हजार रुपये करोड़ का अनाज या तो सड़ गया या चोरी हो

* Not recorded.

गया और 14 करोड़ लोग आज भी इस मुल्क में भूखे सोते हैं। तो क्यों नहीं प्रधान मंत्री जी ऐसी कोई स्कीम बनाकर, यह अनाज जो सड़ने जा रहा है, इसको गरीबों में फ्री बंटवा देते हैं? आपने यह जो कंसेशनल रेट पर जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, एक्सट्रीमली बिलो पावर्टी लाइन के लोगों के लिए जो स्कीम बनायी है उसके बदले इसको फ्री क्यों नहीं बंटवा दिया जाता है बजाए चोरी होने देने के। मेरा यह क्वेश्चन है।

श्री शांता कुमार: सभापति महोदय, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि अनाज के भंडार भरे पड़े हैं। यह देश का सौभाग्य है और उसकी व्यवस्था करने का भी हमने पूरा प्रबंध किया है। जहां तक स्पेस क्रीएट करने का सवाल है, मैंने पहले भी कहा था कि 73 लाख टन के लिए नयी जगह क्रीएट करने का प्रयत्न प्रदेशों को सेवन इयर गारंटी देकर हमने किया है। उसमें से लगभग 60 परसेंट जगह बन गयी है और इस बार के प्रोक्योरमेंट के बाद हमको रखने की कहीं पर कठिनाई नहीं आएगी। तो एक मेरा कहना है, अन्न के भंडार हैं, उनको रखने के लिए पूरी व्यवस्था देश में करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक बात जो कही गई ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Let him complete ...(*Interruptions*).....

श्री शांता कुमार: एक बात जो बार-बार कही गई कि अनाज सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, खराब हो रहा है, तो इस संबंध में मेरा यह कहना है कि सारा अन्न सड़ नहीं रहा है। अगर हमारा अनाज सड़ रहा होता तो 90 लाख टन अनाज हम विदेश में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। आज दुनिया के 25 देश हमारा अनाज खा रहे हैं। और कहीं से कोई शिकायत नहीं है कि हमारा अनाज खराब है। इसलिए सारा अनाज खराब नहीं है। 580 लाख टन में से केवल एक लाख 95 हजार टन डैमेज है। बार-बार यह कहना कि अनाज सड़ रहा है या खराब हो रहा है, तो यह बात ठीक नहीं है। अब इतना अनाज रखा है तो थोड़ा सा तो खराब होगा। लेकिन जितना खराब होता है उसकी हम पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। सभापति जी ...(**व्यवधान**)

पहले मुझे सुनिए, पहले मुझे सुनिए ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Let him reply ..... (*Interruptions*) ..... Let him complete the reply ...(*Interruptions*).....

श्री शांता कुमार: सभापति जी, जो खराब होता है उसको फीड कैटेगरी या अन्य उपयोग के लिए हम नीलम करके दे देते हैं। माननीय सदस्य ने यह कहा कि लोग भूखे हैं, उनकी उन्होंने चिंता प्रकट की, उस चिंता में यह सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी भी आपके साथ शामिल हैं। सभापति महोदय, उसमें कितना कुछ सरकार ने किया है, 36 करोड़ लोग, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको केवल दस किलो सस्ता अनाज दिया जाता था, वह दस किलो से बढ़ा कर पहले बीस, फिर 20 से 25 और आज 35 किलो प्रति परिवार 36 करोड़ लोगों को सस्ते भाव पर दिया जाता है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let him complete... (*Interruptions*)...

श्री शांता कुमार: जो सब से गरीब, 5 करोड़ अति गरीब हैं, उनको 35 किलो प्रति परिवार दो रुपये किलो गेहूं और तीन रूपये किलो चावल दिया जाता है। इसके अलावा 11 प्रदेशों में जब अकाल पड़ा, सभापति जी, सूखे से प्रभावित 11 प्रदेशों में सरकार ने 41 लाख टन अनाज बिल्कुल मुफ्त दे दिया। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने एक नई योजना प्रधान मंत्री रोजगार योजना शुरू की है, उसमें 50 लाख टन अनाज, 5000 करोड़ रुपये का, राज्यों का फूड फॉर वर्क कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। सभापति जी, आप सब मित्रों से आज शिकायत तो मुझे है कि हम जितना अनाज देना चाहते हैं, उतना उठता नहीं है। आप एक सवाल करेंगे कि कीमत ज्यादा है, परचेजिंग पॉवर नहीं है। मान लिया और परचेजिंग पॉवर का मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 करोड़ लोगों को अन्त्योदय अन्न योजना में दो रुपये किलो गेंहूं ओर तीन रुपये किलो चावल 36 करोड़ लोगों को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उनका 4 रुपये 15 पैसे प्रति किलो गेहूं और 5 रुपये 65 पैसे प्रति किलो चावल दिया जा रहा है। सरकार ने एक और निर्णय किया कि एपीएल यानी कोई भी व्यक्ति हमारी दुकान पर आए, हम उसको 35 किलो अनाज देंगे एपीएल को और वह भी भाव नीचे कर दिया 5 रुपये 10 पैसे किलो गेहूं और 7 रुपये 30 पैसे किलो चावल, सब के लिए कर दिया। सभापति जी, मैंने जो कहा कि हमें शिकायत है, यह कीमत की बात छोड़िए हम मिड डे मील में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए मुफ्त देना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त देते हैं, अब यह जो मुफ्त देते हैं, अब यह जो मुफ्त देते है। उसका भी टेक ऑफ केवल 70 प्रतिशत है। इसमें हमारा क्या कसूर है? जो मुफ्त देना चाहते हैं वह भी पूरा नहीं उठता। हम गरीबों के लिए जितना अनाज देना चाहते हैं उसका भी टेक ऑफ नहीं है।...(**व्यवधान**) एक बात, सभापति जी, एक गरीब परिवार को जिंदा रहने के लिए कम से कम 73 किलो की जरूरत है, हम केवल 35 किलो देते हैं, मॉर्केट रेट से बिल्कुल नीचे, वह हंडरेड परसेंट ऑफटेक क्यों नहीं है? मैं इसके लिए बार-बार मुख्य मंत्रियों को कह रहा हूं। यह जो हम 35 किलो देते हैं, कम से कम 73 किलो जिंदा रहने के लिए चाहिए और हम बिल्कुल सस्ती दर पर 35 किलो देते है। और वह भी पूरा नहीं उठता, तो यह पूरा क्यों नहीं उठता? इसमें तो भारत सरकार का कोई दोष नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि आज सारे प्रबन्ध भारत सरकार ने किए हैं, गोदामों के दरवाजे गरीबों के लिए खोले हैं, इसके बावजूद अगर किसी झोपड़ी में भूख है, ... इस के बाद भी अगर किसी झोंपड़ी में भूख का दर्द है तो वह अनाज देने में हमारी कमी के कारण नहीं है, बल्कि गोदामों के कारण है, हमारी कमी के कारण नहीं है।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, this question pertains to Andhra Pradesh, which is related to the issuable and non-issuable stocks. Sir, the question is totally diversified. ....(*Interruptions*).... Anyhow, the discussion on the working of the Ministry of Agriculture is still half-way. We can discuss it when we resume the discussion on the working of the Ministry of Agriculture. This question is related to Andhra Pradesh.

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक: सभापति जी, ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I have permitted Ms. Mabel Rebello.

MISS MABEL REBELLO: Sir, the hon. Prime Minister had announced that 5 kgs. of foodgrains will be given to adolescent girls, free of cost. I think, it was announced in the month of August, 2001. But till today, it has not been implemented. When are they going to implement it? When the Government has got so much of surplus foodgrains in its granary, why are they not giving it to adolescent girls as announced?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, एक और बात स्टॉक के बारे में कही गयी। ...(व्यवधान)

श्री प्रफुल्ल पटेल: सभापति जी, मेरा बहुत वायटल क्युश्चन है और इसी से संबंधित है।

श्री शांता कुमार: सभापति जी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल रिकॉर्ड ऑफटेक 309 लाख टन का हुआ और हमारे पास 620 लाख टन का भंडार था वर्ष 2001 में, यह अब 509 लाख टन हो गया। ...(व्यवधान)... तो ऑफटेक बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट 90 लाख टन हुआ है। इस तरह अब यह देश जो कि 3 साल तक इम्पोर्ट करता था, वह एक्सपोर्ट कर रहा है। ...(व्यवधान) इस के कारण हमारे भंडार खाली हुए हैं, जगह खाली हुई है। सभापति जी, सभी कल्याणकारी योजनाएं जिन्हें राज्य सरकार या स्वयं सेवी संस्थाएं चलाती हैं, उन को हम पहले 5 किलो अनाज सस्ते भाव पर देते थे, उस को बढ़ाकर अब 15 किलो कर दिया गया है। अगर राज्य सरकारें इस प्रकार के केसेज भारत सरकार के पास लाएं तो सरकार ऐसे सारे केसेज में मदद करने के लिए तैयार है।

श्री सभापति: श्री प्रफुल्ल पटेल।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक: सर, गेहूं हम पैदा करते हैं और सवाल ये पूछते हैं।

श्री प्रफुल्ल पटेल: हम भी चावल पैदा करते हैं। सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने हमें बहुत अच्छा चित्र दिखाया है कि देश में खुशहाली है, सब को गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है। आप ने यह भी कहा कि आप के पास इतना सरप्लस स्टॉक है कि आप स्टेट्स को फ्री में देना चाहते हैं। महोदय, क्युश्चन पोल्ट्री सेंटर्स को दिए जाने वाले खाद्यान्नों से संबंधित था जिस के लिए आप फ्री में अनाज देने को तैयार हैं सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट करना होता है। लेकिन क्या मंत्री महोदय, आप को जानकारी है कि जो स्टेट्स इस प्रकार का अनाज उठाते हैं, उस में अधिकतर जिन व्यापारियों को काम दिया जाता है, वह आप के एफ०सी०आई० के गोदामों से एडीबल क्वालिटी का फूड ग्रेन उठा लेते हैं और जो नॉन एडीब ग्रेन है जिसे एक्चुअली उन्हें उठाना चाहिए, वह वहीं रह जाता है। वह सारा माल कैटल फीड या पोल्ट्री फीड के बजाय बाजार में बेचते हैं। इस प्रकार के एक नहीं

अनेक आरोप हो चुके हैं और अनेक स्टेट्स में हो चुके हैं। हमारी स्टेट में भी यह हुआ है और अनेक स्टेट्स में भी यह हुआ है ...(व्यवधान) तो इस बारे में आप के पास जानकारी या शिकायत आई है तो आप ने क्या इंक्वायरी की है?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, भारत सरकार ने इस के लिए इंतजाम किया है कि हमने पर्मानेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जब हमारे गोदाम से अनाज उठाया जाएगा तो ज्वाइंट सैंपलिंग होगी। वहां राज्य सरकार का एक अधिकारी होगा और फूड कार्पोरेशन का एक अधिकारी होगा। वे दोनों ज्वाइंट सैंपलिंग करेंगे कि जो अनाज उठाया जा रहा है, वह खाने योग्य है या नहीं है। यदि वह खराब है तो आप मत उठाइए।...(व्यवधान)... इसलिए अब यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

श्री प्रफुल्ल पटेल: जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस के बारे में बताइए।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Wage Disparity

*722. SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is considerable disparity in rates of minimum wages in various regions of the country ranging from Rs. 19.25 per day in Pondicherry to Rs. 93/- per day in Delhi;

(b) if so, the reasons for such a big variation from region to region;

(c) whether Government have felt the desirability to bring in regional uniformity in respect of minimum wages;

(d) if so, the steps being taken by Government in this regard; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SHARAD YADAV): (a) and (b) Yes, There is disparity in rates of minimum wages in various regions of the country. The disparity is due to differences in socio-economic and agro-climatic conditions, cost of living, productivity etc. Under the Minimum Wages Act, both the Central and State Governments are the appropriate Government to fix, revise and enforce minimum wages in scheduled